आकाशवाणी केन्द्र शिमला

भारतीय प्रसारण निगम

14.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

जीएसटी संग्रह

देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले दस वर्ष में 274 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2024–25 के बीच कर विभाग से जारी रिफंड में 474 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कर दाताओं की संख्या भी 133 प्रतिशत बढ़ी है। रिफंड जारी करने के औसत समय में भी काफी कमी आई है। पिछले दशक में कर प्रशासन में यह सकारात्मक बदलाव डिजिटल बुनियादी ढांचा अपनाने के कारण हुआ है। इससे आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया अधिक आसान, सटीक और तेज हुई है।

पुनर्वास

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास के लिए वन भूमि में घर बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए वन भूमि की आवश्यकता है ताकि वहां स्थायी आवास बनाए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रूपए और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रूपए प्रतिमाह मकान के किराए के रूप में सहायता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री मंडी जिले के थुनाग, करसोग व अन्य क्षेत्रों में बादल फटने से हुए जानमाल के नुकसान से गृह मंत्री को अवगत करवाएंगे और प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज मांगेंगे। सुखविंद्र सिंह सुक्खू का केंद्रीय वित्त मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है।

विमल नेगी

बहुचर्चित विमल नेगी मामले को लेकर आज प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस दौरान मामले को लेकर सी बी आई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। सुनवाई के दौरान आई ए एस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत पर भी निर्णय होगा। इसके अलावा शिमला जिला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी की याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है।

किन्नर कैलाश यात्रा

कल से 30 अगस्त तक चलने वाली किन्नर कैलाश यात्रा के लिए किन्नौर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

15 जुलाई से हमारी जो किन्नर कैलाश होती है उसकी शुरूआत की जाएगी। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मेंडेटरी है रजिस्ट्रेशन प्लस जो कंपलसरी मेडिकल चैकअप है। उसके लिए तांगलिंग एरिया जो हैं जहां हमारे एंटरी प्वाइंट हैं वहां पर सीसीटीवी ऐज वेल ऐज मेडिकल

चेकअप के जो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन जरूरी है जो ग्रीन टैक्स जो लोकल पंचायत द्वारा लगाया जा रहा है उसका मकसद यही है कि कहीं न कहीं क्योंकि ये जो एनवायरमेंट है बहुत परेसटीम नेचुरल एनवायरमेंट है। यहां पर सोलिड वेस्ट कूड़ा करकट न फैलाएं उससे बचाव के लिए ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है।

अवैध कब्जे

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर शिमला जिले में वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी है। जिले के कोटखाई व कुमारसैन में सेब के लगभग 500 पौधों को काटा गया है।

अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिमला जिले में वन भूमि से कब्जे हटाने के लिए वन राजस्व विभाग व प्रशासन ने मुहिम तेज कर दी है। कोटखाई व कुमारसैन में वन भूमि पर बने बगीचों में सब से लगे लगभग 500 पेड़ों को काटा गया है। कुमार सेन के सराहना गांव में भी करीब 320 अवैध पेड़ों को काटा गया है जिसमें से नाशपाती और चेरी के पेड़ शामिल थे। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है।

आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा

मौसम

प्रदेश के अधिकतर भागों में बीती रात हुई वर्षा के बाद आज अधिकांश भागों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िले में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए यैलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में मॉनसून सीज़न के दौरान अब तक 98 लोगों की मौत हुई है। जबकि एक सौ 78 लोग घायल हुए हैं। बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं में विभिन्न स्थानों पर 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के अनुसार प्रदेश में अभी भी भूस्खलन से एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित एक सौ 96 सड़कें और 7 सौ 87 पेयजल योजनाएं ठप्प हैं।